## विचार बिन्दु

आपत्ति मनुष्य बनाती है और संपत्ति राक्षस। –विक्टर ह्यूगो

# अमेरिका - ईरान युद्ध में भारत की रहस्यमयी चुप्पी

28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ किया, तब ऐसा लगा था कि शायद दो-चार दिन में ईरान समर्पण कर देगा। किंतु इस युद्ध का भी वैसा ही हाल होता हुआ दिख रहा है जैसा रूस और यूक्रेन के मध्य हो रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध को चार वर्ष हो चुके हैं और अभी भी समाप्त होने का नाम नहीं है।

इजराइल ने पहले ही दिन ईरान के एक स्कूल पर बमबारी की जिसमें लगभग 200 छोटी लड़कियां मारी गईं। अब तक इस युद्ध को 9 दिन हो चुके हैं। लाखों-करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है और हजारों परिवार बर्बाद हो चुके हैं। इसके बावजूद युद्ध की तीव्रता निरंतर बढ़ती जा रही है। गनीमत यही है कि अभी तक इसमें चीन और रूस सीधे रूप से शामिल नहीं हुए हैं। ईरान ने अपनी सैनिक क्षमता का पूरा परिचय इसमें दिया है। अमेरिका ने युद्ध के प्रारंभ में ही ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई, सेनापति एवं उनके सभी सहायकों की हत्या कर दी। इस पूरे प्रकरण के दौरान भारत सरकार ने चुप्पी साध रखी है।

भारत, सदैव मानवीय और नैतिक मूल्यों का संवाहक रहा है और प्रधानमंत्री मोदी इसकी दुहाई लगभग हर संबोधन में देते रहे हैं। भारत, सदैव किसी देश पर आक्रमण और उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का विरोध करता रहा है। यह पहली बार है जब अमेरिका-इजरायल द्वारा अचानक ईरान पर हमला किया गया, उसके बावजूद भारत ने इसकी निंदा तक नहीं की है। ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्ला खामनेई की हत्या के बावजूद भारत ने लंबे समय तक इस पर शोक तक नहीं प्रकट किया। भारत द्वारा इस प्रकार चुप्पी साध लेने के कई अर्थ विश्लेषकों द्वारा निकाले जा रहे हैं। कुछ का मानना है कि यह अमेरिका के हाथों ब्लैकमेल होने जैसा है।

अमेरिका ने ईरान पर हमला करने का मुख्य आधार ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना बताया था। यह उल्लेखनीय है कि 25 फरवरी 2026 को ही, अर्थात युद्ध से केवल दो दिन पूर्व ओमान की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच इस बात का समझौता लगभग हो ही चुका था कि ईरान, यूरेनियम संवर्धन का कार्यक्रम बंद कर देगा। इस पर एक-दो दिन में हस्ताक्षर होने थे।इसके बाद कोई कारण नहीं था कि अमेरिका, ईरान पर अचानक हमला कर दे। इसी से स्पष्ट है कि यह तो केवल बहाना था। वास्तव में अमेरिका ईरान को तहस-नहस करना चाहता था।

अमेरिका ने कुछ सालों पूर्व 2003 में इराक पर हमला इस बहाने किया था कि इराक के पास रासायनिक हथियार थे। यह बात किसी भी जांच से सही नहीं निकली। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने लीबिया, सूडान, सोमालिया, यमन, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि कई देशों पर केवल अपनी साम्राज्यवादी विस्तार की नीति के अंतर्गत आक्रमण किया और इन देशों की सार्वभौमिकता पर आघात किया।

ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या करना और उसके 40 प्रमुख नेताओं को एक साथ मार देना, किसी भी देश के आंतरिक मामलों में स्पष्ट दखल है। ऐसा करने की कोई ठेकेदारी अमेरिका को कहीं से नहीं मिली है। इसके उलट, संयुक्त राष्ट्र की सभी मर्यादाओं को अमेरिका ने तार-तार कर दिया है, विशेष कर ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद।

यदि हम भारत की विदेश नीति का इतिहास देखें तो पाएंगे कि भारत ने सदैव उस देश का साथ दिया है जिससे मानवीय मूल्यों की रक्षा करने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए 1953 में जब ईरान में रूसी सैनिकों ने प्रवेश किया, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रूस को अपनी सेना ईरान से हटाने के लिए कहा था, इसके बावजूद कि उस समय भारत और रूस के बीच दोस्ती के संबंध थे। इसी प्रकार, 1994 में जब नरसिंहराव सिंह की सरकार थी, उस समय इस्लामी देशों के संगठन (ओ आई सी) द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोप में भारत के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया गया था। इसके पारित होने के लिए ईरान के भी हस्ताक्षर आवश्यक थे। भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री दिनेश सिंह को बीमारी के बावजूद ईरान भेजा गया जिन्होंने वहां के राष्ट्रपति को तैयार इस बात के लिए किया कि वह इस निंदा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर न करें। भारत की बात मान कर ऐसा न कर ईरान ने भारत का साथ दिया, जिसके कारण निंदा प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। अपनी विदेश नीति को किसी के दबाव के बिना और किसी भी गुट में शामिल हुए बगैर मानवीय मूल्यों के आधार पर और स्वतंत्र सार्वभौमिकता के सिद्धांत के आधार पर भारत तैयार करता रहा है। उसी अनुसार पालन भी करता रहा है।

**भारत, सदैव मानवीय और नैतिक मूल्यों का संवाहक रहा है और प्रधानमंत्री मोदी इसकी दुहाई लगभग हर संबोधन में देते रहे हैं। भारत, सदैव किसी देश पर आक्रमण और उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का विरोध करता रहा है। यह पहली बार है जब अमेरिका-इजरायल द्वारा अचानक ईरान पर हमला किया गया, उसके बावजूद भारत ने इसकी निंदा तक नहीं की है।**

हाल ही में अमेरिका के सामने जिस प्रकार भारत ने आत्म समर्पण कर दिया है, वह उसकी विदेश नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार-बार यह कहते रहे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष को समाप्त करवाया किंतु भारत की ओर से न तो किसी मंत्री ने न किसी अधिकारी ने ट्रंप के बयान का खंडन किया और यह कहने का साहस किया कि ट्रंप की इस युद्ध विराम में किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं थी। अमेरिका से होने वाली ट्रेड डील की घोषणा भी ट्रंप ने अपनी ओर से एक तरफा कर दी। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प द्वारा लगाए गए मनमाने टैरिफ को खारिज कर दिया और इसी कारण भारत, अमेरिका की ट्रेड डील पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। इस ट्रेड डील के अनुसार भारत पर टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया किंतु अन्य शर्तों के साथ यह शर्त भी लगा दी कि भारत रूस से कच्चा तेल आयात नहीं करेगा। ट्रेड डील पर हस्ताक्षर नहीं होने के बावजूद अमेरिका ने यह घोषणा की कि भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए एक महीने की अनुमति दी गई है।यह उल्लेखनीय है कि भारत को रूस से बहुत कम कीमत पर कच्चा तेल मिलता था और वहां से तेल की खरीद बंद करने पर भारत में तेल की कीमतें बहुत बढ़ने की संभावना थी। इसके बावजूद भारत ने इस डील पर सहमति दी थी। इसी बीच, ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया। अमेरिका ने अब एक प्रकार से भारत को छूट देते हुए घोषणा की, कि एक महीने तक वह रूस से तेल खरीद सकता है। अमेरिका का यह आचरण भारत की स्वतंत्रता पर एक प्रकार से हमला ही कहा जाएगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि रूस से तेल खरीदने की अनुमति ऊंचे दामों पर दी गई है क्योंकि वही तेल खरीदा जाएगा जो टैंकरों में अभी समुद्र में है। रूस से खरीद की पूर्व शर्तों के अनुसार भारत को रियायती कीमत पर तेल मिलना था किंतु अब केवल वही तेल उपलब्ध होगा जो अभी समुद्र में टैंकरों में है।

क्या भारत ने इस प्रकार से अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण सा नहीं कर दिया है? इसका कोई प्रत्यक्ष कारण समझ में नहीं आता है। आशंकाएं अवश्य उत्पन्न होती हैं। एक आशंका यह है कि भारत के शीर्ष नेताओं की कोई कमजोर नस अमेरिका के हाथ में है और ट्रंप उसका उपयोग करके भारत को ब्लैकमेल कर रहा है। यह भी संभव है जिस प्रकार से यहां से कुछ बड़े नेताओं और उद्योगपतियों का नाम ऐप्सटीन फाइल में आया उससे ध्यान भटकाने के लिए अमेरिका ऐसा आचरण कर रहा है। अमेरिका जो चाहे, वह करे, उस पर यह चुप्पी, मौन सहमति देने के समान है। आप चाहे जो कर लें, हम आपके सामने कुछ न कहेंगे न विरोध करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह व्यवहार चुनाव पूर्व की उनकी उस मुद्रा के बिल्कुल विपरीत है, जब वे कहते थे कि हम अन्य देशों से आँख से आँख मिला कर बात करेंगे। उनकी छप्पन इंच की छाती का भी बहुत बखान किया जाता है। ऐसा कहने वाले प्रधानमंत्री अब क्यों इस प्रकार से कमजोर दिखाई दे रहे हैं, इसका कोई कारण देश की जनता को समझ में आ नहीं रहा है।

उचित होगा लोकसभा का सत्र जो सोमवार से प्रारंभ हुआ है, उसमें विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री, स्वयं, इस पूरे परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति स्पष्ट करें, ताकि देश वासी आश्वस्त हो सकें कि हमने अपनी आत्म सम्मान को सुरक्षित रखते हुए जो विदेश नीति अब तक बनाई है, जिसमें भारत के हित को सर्वोपरि रखने की बात की गई और देश को स्वाभिमान के साथ चलाने की बात की है, उसके बारे में किसी प्रकार का कोई समझौता देश के नेताओं ने नहीं किया है, क्यू विशेष कर अमेरिका के सामने। वैसे भी ईरान में जो कुछ भी हुआ, अंतरराष्ट्रीय कानून का पूरा उल्लंघन था और इस कारण भारत को प्रारंभ से उसका विरोध करना चाहिए था।

इस संदर्भ में एक और घटना उल्लेखनीय है। ईरान का एक सैन्य जहाज भारत के निमंत्रण पर विशाखापट्टनम आया था। जैसे ही यह मेहमान जहाज़ पुनः ईरान जा रहा था, उससे पूर्व ही ईरान-अमेरिका युद्ध प्रारंभ हो चुका था। भारतीय समुद्री सीमा के समीप ही श्रीलंका की सीमा में जब यह जहाज ;IRIS ,DENA " जा रहा था तो अमेरिका ने उस पर पनडुब्बी से हमला करके उसे पानी में डूबा दिया। इस हमले में 87 ईरानी सैनिक मारे गए और कई अन्य लापता हैं। भारत ने इस पर भी विरोध दर्ज नहीं कराया।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विस्तारवादी उल जुलूल बयानों का कनाडा जैसे छोटे देश के प्रधानमंत्री कार्नी तक ने विश्व व्यापार संगठन में संबोधन के दौरान भरपूर खुले आम विरोध किया, वहीं 150 करोड़ लोगों के देश भारत के प्रधानमंत्री की चुप्पी अभी रहस्य ही बनी हुई है। भारत, वास्तव में विश्वगुरु कहलाने का अधिकारी तब ही होगा जब वह सच के साथ खड़ा दिखाई देगा और वह अनैतिक और अकारण युद्ध प्रारंभ करने वाले देश की निंदा करने का साहस दिखाएगा।

**–अतिथि सम्पादक,**
**राजेन्द्र भाणावत**
**( पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी )**

# जल संकट से जल-सुरक्षा की ओर बढ़ता राजस्थान

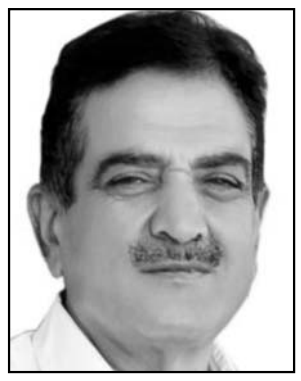

**डॉ. रामप्रताप**

राजस्थान की पहचान सदियों से रेतीले विस्तार, अल्प वर्षा और जल की कठिन उपलब्धता से जुड़ी रही है। यहां पानी जीवन की सबसे बड़ी चुनौती रहा है। मरुधरा की धरती पर पानी की एक बूंद के लिए मीलों का सफर तय करती पणिहारियों के पदचाप और सूखे कंठों की पुकार राजस्थान के सामाजिक इतिहास का स्थायी चित्र रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल संरक्षण के राष्ट्रीय विजन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास मरुधरा की प्यास बुझाने की दिशा में निर्णायक साबित हो रहे हैं। अब तस्वीर तेजी से बदलती दिखाई दे रही है। आधुनिक तकनीक, दूरदर्शी नीतियों और समन्वित प्रयासों के कारण राजस्थान धीरे-धीरे जल संकट से जल-सुरक्षा की दिशा में बढ़ रहा है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, किंतु यहां जल संसाधन अत्यंत सीमित हैं। देश के कुल भूभाग का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में है, जबकि यहां उपलब्ध जल संसाधन कुल का लगभग 1 प्रतिशत ही हैं। औसत वर्षा भी लगभग 500 मिमी से कम है, जबकि पश्चिमी जिलों में यह 200 मिमी से भी नीचे चली जाती है। प्रदेश के कई हिस्सों में भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है और अनेक क्षेत्रों में पानी खारा या फ्लोराइड युक्त होने के कारण पीने योग्य भी नहीं रहता।

यही कारण है कि जल प्रबंधन राजस्थान के विकास की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में स्थापित किया है। जल है तो कल है के मंत्र के साथ उन्होंने जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, अटल भूजल योजना, प्रति बूंद अधिक फसल जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से जल संरक्षण और जल उपलब्धता को व्यापक जन आंदोलन का रूप दिया है। इसी राष्ट्रीय दृष्टि को आधार बनाकर राजस्थान में भी जल संसाधनों के विकास और संरक्षण की दिशा में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रस्तुत बजट 2026-27 में जल संरचना को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। यह बजट प्रदेश के आठ करोड़ नागरिकों की प्यास बुझाने का एक ठोस संकल्प प्रतीत होता है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में राजस्थान को जल-सुरक्षित राज्य के रूप में स्थापित किया जाए। इसके लिए दीर्घकालिक परियोजनाओं के साथ-साथ पारंपरिक जल स्त्रोतों के संरक्षण और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

प्रदेश में प्रस्तावित और प्रगति पर चल रही विभिन्न नदी-लिंक परियोजनाएं राजस्थान के जल भूगोल को बदलने की क्षमता रखती हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना पूर्वी राजस्थान के लिए एक जीवनरेखा के रूप में उभर रही है। इस योजना के माध्यम से अधिशेष जल को जल-अभाव वाले क्षेत्रों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे न केवल पेयजल उपलब्धता बढ़ेगी बल्कि सिंचाई क्षेत्र में भी उल्लेखनीय विस्तार होगा।

इसी प्रकार विभिन्न जलाशयों और नहर प्रणालियों के एकीकरण के लिए मल्टी-रिजर्वायर इंटीग्रेशन मॉडल विकसित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से परवन बांध के जल को बीसलपुर, जयसमंद और जवाई जैसे प्रमुख जलाशयों तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। यह जल वितरण की दृष्टि से एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में हरित क्रांति की आधारशिला रखने वाली इंदिरा गांधी नहर परियोजना का आधुनिकीकरण भी राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। लगभग 2500 किलोमीटर क्षेत्र में नहर प्रणाली को आधुनिक तकनीक से सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके साथ-साथ सेम की समस्या से लगभग 50 हजार हेक्टेयर भूमि को मुक्त कराने की योजना किसानों के लिए अत्यंत राहतकारी साबित होगी। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा में तालाब, बावड़ियां और जलाशय सदियों से जल संरक्षण के प्रमुख साधन रहे हैं। राज्य सरकार ने इस विरासत को पुनर्जीवित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, टोंक, झालावाड़ और उदयपुर जैसे जिलों में लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत से जलाशयों के पुनरुद्धार का कार्य किया जा रहा है। इससे न केवल जल संग्रहण क्षमता बढ़ेगी बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी और पर्यटन को भी लाभ मिलेगा। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जैसे सीमावर्ती जिलों में जल उपलब्धता हमेशा बड़ी चुनौती रही है। इन क्षेत्रों के लिए जियो-ग्रिड तकनीक तथा खारे-मीठे जल के मिश्रण की नई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इन पहलों का उद्देश्य दूरस्थ गांवों तक सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हो सके।

**तकनीक और हरित ऊर्जा का समावेश**

जल प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा का उपयोग भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। परियोजनाओं में सौर ऊर्जा आधारित संयंत्रों की स्थापना से ऊर्जा लागत कम होगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा। साथ ही सिंचाई मित्र ऐप, ऑटोमेटेड गेट सिस्टम और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्थाओं से जल वितरण प्रणाली को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा रहा है।

जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर तक नल से जल पहुंचाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने लगभग 10 लाख अतिरिक्त घरों तक पाइपलाइन से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह पहल केवल जल आपूर्ति तक सीमित नहीं है। यह ग्रामीण महिलाओं के श्रम को कम करने, स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाने और सामाजिक गरिमा को सुदृढ़ करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

जल संसाधनों का सुदृढ़ प्रबंधन पेयजल समस्या का समाधान करने के साथ ही कृषि, उद्योग, पर्यटन और शहरी विकास के लिए भी नई संभावनाएं खोलता है।औद्योगिक क्षेत्रों के लिए छह मेगा वाटर स्टोरेज यूनिट्स के निर्माण की योजना राज्य को निवेश के लिए अधिक आकर्षक बनाएगी। इससे उद्योगों को स्थायी जल उपलब्धता सुनिश्चित होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। स्पष्ट है कि राजस्थान अब केवल जल संकट से जूझने वाला प्रदेश नहीं रहा, बल्कि जल प्रबंधन के अभिनव मॉडल विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

तालाबों के पुनर्जीवन से लेकर नदी-लिंक परियोजनाओं तक, सौर ऊर्जा आधारित पंपिंग से लेकर डिजिटल जल प्रबंधन तक की यह समग्र दृष्टि दर्शाती है कि राज्य सरकार मरुधरा की शिराओं में जल रूपी अमृत प्रवाहित करने के लिए गंभीर और प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे ये प्रयास आने वाले वर्षों में राजस्थान के विकास की नई कहानी लिख सकते हैं। संभव है कि जिस प्रदेश की पहचान कभी पानी के अभाव से होती थी, वही प्रदेश भविष्य में जल प्रबंधन के सफल मॉडल के रूप में देश और दुनिया के सामने उदाहरण बनकर उभरे। मरुधरा की प्यास बुझाने की यह यात्रा केवल जल उपलब्धता की कहानी नहीं है, यह संघर्ष से समृद्धि तक पहुंचने की एक प्रेरक गाथा भी है।

**–डॉ. रामप्रताप,**
**पूर्व जल संसाधन मंत्री,**
**राजस्थान**

# पश्चिम एशिया के संकट की नई आहट : ईरान व अमेरिका टकराव और उसके दूरगामी प्रभाव

**डॉ. नीरज रावत**

पश्चिम एशिया एक बार फिर अनिश्चितता और तनाव के दौर से गुजर रहा है। बीते दिनों में जिस तेजी से सैन्य गतिविधियाँ बढ़ी हैं और राजनीतिक बयानबाज़ी तीखी हुई है, उसने इस पूरे क्षेत्र को एक बार फिर वैश्विक चिंता का केंद्र बना दिया है। वॉशिंगटन से आ रहे संकेत बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प का प्रशासन ईरान के प्रति दबाव की नीति को और कड़ा करने के पक्ष में दिखाई देता है। कभी और भी बड़ी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी, तो कभी ईरान में सत्ता परिवर्तन उद्देश्य बताना - इन सब कारणों ने इस संकट को केवल एक द्विपक्षीय टकराव से कहीं अधिक जटिल बना दिया है।

परंतु इस पूरी बहस में एक बुनियादी सवाल अक्सर पीछे छूट जाता है कि यदि ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश होती है, तो उसके बाद स्थिरता कैसे स्थापित की जाएगी? इतिहास हमें बताता है कि किसी शासन को हटाना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है, लेकिन उसके बाद स्थिर व्यवस्था कायम करना कहीं अधिक कठिन और अनिश्चित प्रक्रिया होती है।

इस संदर्भ में 2003 का ईराक युद्ध एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। उस युद्ध ने सद्दाम हुसैन के शासन का अंत तो कर दिया, लेकिन इसके बाद इराक लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता, सांप्रदायिक हिंसा और संस्थागत विघटन से जूझता रहा। इसी तरह 2011 में लीबियाई युद्ध के दौरान मुअम्मर गद्दाफी का शासन समाप्त हुआ, परंतु लीबिया स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तित नहीं हो पाया। इसके बजाय वहां वर्षों तक सत्ता संघर्ष, मिलिशिया हिंसा और राजनीतिक विखंडन की स्थिति बनी रही। इन अनुभवों को देखते हुए ईरान के संदर्भ में सत्ता परिवर्तन की चर्चा और भी अधिक संवेदनशील हो जाती है। ईरान न तो इराक जैसा है और न ही लीबिया जैसा। लगभग नौ करोड़ की आबादी वाला यह देश एक गहरी ऐतिहासिक पहचान और मजबूत संस्थागत संरचना रखता है। साथ ही इसकी भौगोलिक स्थिति (फारस की खाड़ी के प्रवेश द्वार पर) इसे वैश्विक ऊर्जा राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है।

संघर्ष के नौवें दिन की घटनाओं ने इस संकट की गंभीरता को और स्पष्ट कर दिया। मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरों ने खाड़ी क्षेत्र में असुरक्षा की भावना को बढ़ाया, जबकि तेल बाजारों में तुरंत प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ ही समय में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव शुरू हो गया और समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएँ सामने आईं। यह स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि फारस की खाड़ी से होकर दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल और गैस की आपूर्ति होती है। इन घटनाओं के बीच एक दिलचस्प कूटनीतिक पहलू भी सामने आया है, ईरान द्वारा अपने कुछ पड़ोसी देशों से माफी माँगना। क्षेत्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ईरान ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि उसका संघर्ष सीधे तौर पर उन देशों के साथ नहीं है और यदि किसी सैन्य कार्रवाई से उनके क्षेत्र या हित प्रभावित हुए हों तो उसके लिए खेद व्यक्त किया गया।

यह कदम केवल औपचारिक कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं माना जाना चाहिए। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संदेश भी छिपा है। ईरान भलीभांति जानता है कि यदि खाड़ी के अरब देश पूरी तरह उसके विरुद्ध एकजुट हो जाते हैं तो उसकी स्थिति और अधिक कठिन हो सकती है। इसलिए वह यह संकेत देना चाहता है कि उसका मुख्य टकराव अमेरिका और उसके कुछ सहयोगियों से है, न कि पूरे क्षेत्र से।

कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि अमेरिका इस टकराव में केवल इस्राइल के समर्थन में सक्रिय नहीं हुआ है। इसके पीछे व्यापक क्षेत्रीय समीकरण भी हो सकते हैं, जिनमें शक्ति संतुलन और सऊदी अरब की सुरक्षा चिंताएँ भी शामिल हैं। ईरान और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा ने पश्चिम एशिया की राजनीति को बार-बार प्रभावित किया है। फिर भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है कि, क्या अमेरिका वास्तव में तेहरान की धरती पर अपने सैनिक उतारने का जोखिम उठाएगा? सैन्य शक्ति के लिहाज से अमेरिका निस्संदेह कहीं अधिक मजबूत है, लेकिन ईरान जैसे बड़े और जटिल देश में जमीनी युद्ध का अर्थ एक लंबा, महँगा और अनिश्चित संघर्ष हो सकता है। इस पूरे परिदृश्य को भारत के दृष्टिकोण से भी समझना आवश्यक है। भारत के लिए पश्चिम एशिया केवल एक दूर का भू-राजनीतिक क्षेत्र नहीं है। यह हमारी ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक हितों और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा से सीधे जुड़ा हुआ है। भारत अपने कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है, इसलिए खाड़ी क्षेत्र में किसी भी तरह की अस्थिरता का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं। यदि क्षेत्रीय तनाव बढ़ता है तो उनकी सुरक्षा और संभावित निकासी जैसी चुनौतियाँ भी सामने आ सकती हैं। भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण आयाम चाबहार बन्दरगाह परियोजना है, जो भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक वैकल्पिक संपर्क प्रदान करती है। यदि ईरान में अस्थिरता बढ़ती है तो इस परियोजना और उससे जुड़े व्यापक क्षेत्रीय संपर्क प्रयासों पर भी असर पड़ सकता है। भारत की विदेश नीति लंबे समय से संतुलन और संवाद पर आधारित रही है। एक ओर भारत ने इस्राइल के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को मजबूत किया है, वहीं दूसरी ओर ईरान और खाड़ी के अरब देशों के साथ भी सहयोग बनाए रखा है। यही संतुलन भारत की कूटनीतिक ताकत भी है और उसकी चुनौती भी।

अंततः इस पूरे संकट का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न केवल युद्ध का नहीं है, बल्कि उस भविष्य का है जो युद्ध के बाद आकार लेता है। यदि सत्ता परिवर्तन की रणनीति अस्पष्ट और अधूरी रही, तो उसका परिणाम केवल एक सरकार के पतन तक सीमित नहीं रहेगा। वह पूरे क्षेत्र को लंबे समय तक अस्थिरता और प्रतिस्पर्धा के दौर में धकेल सकता है। ऐसे समय में कूटनीति, संयम और दूरदर्शिता ही वह रास्ता है जो इस संकट को एक व्यापक वैश्विक चुनौती में बदलने से रोक सकता है। युद्ध कभी-कभी कुछ दिनों में शुरू हो जाता है, लेकिन उसके परिणाम कई पीढ़ियों तक महसूस किए जाते हैं।

**–डॉ. नीरज रावत, जयपुर।**

# स्वाभिमान से स्वावलम्बन तक ( सत्य घटना )

**अभिरुचि शर्मा**

ढलती सांझ की लंबी होती परछाइयां, भगवान भास्कर अस्ताचलगामी हो रहे थे। जीर्ण-शीर्ण वस्त्र धारण करे 25-30 वर्ष की वह युवती जो कि एक पैर से घिसट-घिसट कर चल रही थी, उसके चेहरे पर जीवन से पराजय के भाव दृष्टिगोचर हो रहे थे। न जाने किस ईश्वरीय प्रेरणा से वह मेरे पास आकर काम मांगने लगी, कहा–"आप मुझे कुछ भी काम दें, कुछ भी रुपये दें, पर मेरे जीवन को सहारा दें।"

मैंने पूछा–"क्या कर सकोगी?" उसने कहा–"आप जो कहेंगी"। मैंने कहा–"तुम्हारा तो एक हाथ भी सही से काम नहीं कर सकता"।

वह बोली–'17-18 वर्ष की उम्र में लड़की होने पर मुझे लकवा मार गया, (वाह रे बाल विवाह!) आप काम करवाइये तो सही"।

मैंने भी सोचा-ठीक है...इसे थोड़ा सफाई का एवं जो कुछ यह खुशी से कर सके ऐसा काम दे देते हैं। मैंने अपने कपड़ों में से कुछ ठीक से कपड़े भी उसे दिए। दूसरे दिन सुबह सही 6 बजे उसने घंटी बजाई और तत्परता से बरतन साफ करने लगी। फिर झाड़ू लगाकर चीजों को व्यवस्थित कर बोली–"दीदी, देख लीजिए काम ठीक से किया है ना"?

मुझे आश्चर्य हुआ, जीने की इच्छा ना कुछ होने पर भी बहुत कुछ होने की आश्वस्तता उसकी अपंगता, असहायता उसके काम की राह में आड़े नहीं आई। उसका कमजोर और लाचार शरीर व दो छोटे-छोटे बच्चे...लड़की 8 साल की और लड़का लगभग 2 साल का। मैंने बच्चों के कुछ कपड़े और उसके घर के राशन का इंतजाम भी किया। पता नहीं किस देवयोग से वह हमारे पूजाघर के ठाकुरजी के बरतन साफ करती और मुझसे कहती–'दीदी, मेरी पेंशन करा दीजिए'।

तब मैंने सरपंच से फोन कर पता किया और किसी काम से जयपुर आयी तो उसका दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बनवा दिया और वहीं किसी स्कीम से एक सिलाई मशीन भी दिलवा दी।

उसकी कर्मनिष्ठा और मुझ में श्रद्धा से कुछ ऐसे बानक बने कि उसको खादी भंडार से सूत कातने का काम मिला और शनैःशनैः उसका वह हाथ भी ठीक होने लगा, जो कि उसके जीवनयापन का आधार बना। लाचारियों से रुसवाइयां नहीं वरन परिस्थिति से सामंजस्य बिठा अपने बच्चों को पढ़ाने की ललक।

विधाता ने भी उसका साथ दिया। घर में लाइट नहीं, लड़की अंधेरे में कैसे पढ़ती? पैसा आने पर लाइट का कनैक्शन ले लिया। बैंक में खाता खुलवाने के लिए आधार कार्ड बनवाने के लिए वह कितना भटकी। मुझे भी उस पर तरस आने लगा, खाता खुला - आमदनी होने लगी - पेंशन भी आने लगी...अंततोगत्वा स्वाभिमान स्वावलंबी हो गया।

**–अभिरुचि शर्मा,**
**स्वतंत्र लेखिका।**

## राशिफल

**पंडित अनिल शर्मा**

**मंगलवार 10 मार्च, 2026**

चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, अनुराधा नक्षत्र सायं 7:05 तक, हर्षण योग प्रातः 8:21 तक, विष्टि करण दिन 12:41 तक, चन्द्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

**गृह स्थितिः** सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-कुम्भ, बुध-कुम्भ, गुरू-मिथुन, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज राजयोग सूर्योदय से सायं 7:05 तक है। रवियोग सायं 7:05 तक है। आज भद्रा दिन 12:41 तक है। आज रांधा पुआ है।

**श्रेष्ठ चौघड़ियाः** चर 9:42 से 11:09 तक, लाभ-अमृत 11:09 से 2:05 तक, शुभ 3:33 से 5:01 तक।

**राहूकालः** 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:46, सूर्यास्त 6:29

**मेष**
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा में परेशानी हो सकती है।

**वृष**
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

**मिथुन**
स्वास्थ्य संबंधित परेशानी दूर होने लगेगी। दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**कर्क**
परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

**सिंह**
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।